vinetur

यूरोपीय संघ की सरकारें आंशिक कृषि समझौते के करीब, शराब क्षेत्र के नियम अब भी अनसुलझे

मंत्रियों का लक्ष्य अक्टूबर के अंत तक ईयू के गैर-वित्तीय कृषि सुधारों पर सहमति पक्की करना है, लेकिन शराब क्षेत्र की सहायता पर मतभेद कायम हैं।

बुधवार, 7 अक्टूबर 2026



यूरोपीय संघ की सरकारें इस सप्ताह संघ की कृषि नीति और बाजार नियमों में बदलावों पर आंशिक राजनीतिक समझौते के करीब पहुंचीं, लेकिन अक्टूबर के अंत की समय-सीमा से पहले बातचीत में शराब क्षेत्र को सहायता देना अब भी प्रमुख अनसुलझे मुद्दों में शामिल है।

27 सदस्य देशों के कृषि विशेषज्ञों ने 5 अक्टूबर को ईयू की कृषि संबंधी विशेष समिति में बैठक की और साझा कृषि नीति (CAP) तथा कृषि उत्पादों के साझा बाजार संगठन को नियंत्रित करने वाले विनियमन पर समझौते की दिशा में प्रगति की। लक्ष्य है कि महीने के अंत तक मुख्य राजनीतिक रूपरेखा तय कर ली जाए, इससे पहले कि कृषि मंत्री 26 और 27 अक्टूबर को लक्ज़मबर्ग में मिलें।

CAP को लेकर कई मुद्दे अब भी खुले हैं। बातचीत में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि साझा ईयू ढांचे को बरकरार रखते हुए नियम लागू करने में सदस्य देशों को कितनी छूट मिलनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल युग्मित आय सहायता के हिस्से, नियंत्रण दरों और कृषि सहायता से जुड़ी नई शर्तों पर भी चर्चा कर रहे हैं।

बाजार विनियमन के मामले में, आयरिश अध्यक्षता द्वारा तैयार किए गए नवीनतम समझौता मसौदे को सदस्य देशों का व्यापक समर्थन मिला है, लेकिन अधिकारी अब भी कई तकनीकी और राजनीतिक बारीकियों पर काम कर रहे हैं। कई राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल शराब क्षेत्र में क्षेत्रीय हस्तक्षेप, उत्पादक संगठनों द्वारा संचालित परिचालन कार्यक्रमों के जरिए लागू किए जाने वाले क्षेत्रीय उपायों के वित्तपोषण और भांग से जुड़े नियमों में और बदलाव चाहते हैं—खास तौर पर वहां, जहां ये राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों से मेल खाते हैं।

दोनों मसौदा दस्तावेज़ 12 और 19 अक्टूबर को होने वाली अगली बैठकों में कृषि संबंधी विशेष समिति के सामने फिर रखे जाएंगे। इसके बाद मंत्रियों से उम्मीद है कि वे उस समझौते को अंतिम रूप देंगे जिसे ब्रसेल्स 'आंशिक सामान्य रुख' कहता है। इसका अर्थ है पैकेज के गैर-वित्तीय हिस्सों पर व्यापक राजनीतिक सहमति।

शराब क्षेत्र को लेकर बाकी मतभेद सीमित दायरे की कृषि नीति बहस से कहीं अधिक मायने रखते हैं। जिन नियमों पर बातचीत हो रही है, वे यह तय कर सकते हैं कि पूरे ईयू में शराब उत्पादकों और उत्पादक समूहों को सहायता कैसे मिलेगी, वे बाजार उपायों का वित्तपोषण कैसे करेंगे और सामूहिक कार्यक्रम कैसे आयोजित करेंगे। इससे पेय क्षेत्र में निवेश के फैसलों और व्यावसायिक योजना पर असर पड़ सकता है, खासकर उन वाइनरी और उत्पादक समूहों पर जो ईयू समर्थित हस्तक्षेप उपायों पर निर्भर हैं।

यह चर्चा ऐसे समय हो रही है जब ब्रसेल्स अन्य नीतिगत माध्यमों से शराब क्षेत्र को सीधे समर्थन देते रहने के तरीके पर भी विचार कर रहा है। कृषि नीति वार्ता वाले दिन ही यूरोपीय संसद की कृषि समिति ने ईयू की कृषि-खाद्य प्रचार नीति पर स्वप्रेरित रिपोर्ट को 37 के मुकाबले 7 मतों से मंजूरी दी ; एक सदस्य ने मतदान में भाग नहीं लिया। सांसदों ने कहा कि शराब और मांस को ईयू प्रचार निधि के पात्र क्षेत्रों में बने रहना चाहिए।

संसद की समिति के सदस्यों ने निधि तक पहुंच आसान बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करने की भी मांग की। उनका कहना था कि बाजार की परिस्थितियां बदलने या भू-राजनीतिक घटनाओं से व्यापार बाधित होने पर मंजूर अभियानों में बाद में बदलाव करना आसान होना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम मंजूर हो जाने के बाद अभियानों, उत्पादों, बजट या लक्षित बाजारों को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए अधिक छूट का भी समर्थन किया।

शराब उत्पादकों के लिए यह अलग बहस इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इससे ईयू के भीतर चल रहे व्यापक राजनीतिक संघर्ष का संकेत मिलता है : क्या बजट और बाजार नीति में शराब को अन्य कृषि क्षेत्रों की तरह ही माना जाना चाहिए। शराब को पात्र बनाए रखने के समर्थकों का तर्क है कि समान व्यवहार का सिद्धांत सभी कृषि क्षेत्रों पर लागू होना चाहिए। संसद की समिति की रिपोर्ट को अब भी पूर्ण सदन से मंजूरी मिलनी बाकी है।

अक्टूबर के अंत का लक्ष्य मतभेद कम करने के लिए ईयू अधिकारियों के पास सीमित समय छोड़ता है। पैकेज को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक समर्थन दिख रहा है, लेकिन अनसुलझे सवाल बताते हैं कि साझा ईयू नियमों का दायरा कितना होना चाहिए और राष्ट्रीय सरकारों को व्यवस्था के अनुरूप बदलाव करने की कितनी गुंजाइश मिलनी चाहिए—इस पर सदस्य देशों में अब भी मतभेद हैं। शराब से जुड़े हिस्से में यह संतुलन खास तौर पर संवेदनशील साबित हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि सहायता, बाजार प्रबंधन और उत्पादक संगठनों का वित्तपोषण संघ के सबसे अधिक राजनीतिक रूप से चर्चित कृषि उद्योगों में से एक के भीतर एक साथ आते हैं।

यदि मंत्री इस महीने के अंत में बाकी मतभेद दूर कर पाते हैं, तो इससे परिषद के लिए उस सुधार पैकेज पर बातचीत की रूपरेखा तय होगी जो पूरे ईयू में कृषि सहायता देने के तरीके को प्रभावित करेगा। शराब उद्योग में उत्पादक, सहकारी संस्थाएं और पेय कंपनियां क्षेत्रीय हस्तक्षेपों और उत्पादक कार्यक्रमों के वित्तपोषण से जुड़े अंतिम शब्दों पर करीबी नजर

रखेंगी, क्योंकि वे आकलन करेंगी कि ईयू के भविष्य के सहायता नियम यूरोपीय बाजार को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं।